

खेती के लिये आवश्यक लोहा

+

\* १८१६. { श्री विभूति मिश्र :  
श्री रामी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती के लिये लोहे की सारी आवश्यकता पूरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ और १९५९ में विभिन्न राज्यों को लोहे का कितना कोटा दिया गया, और लोहा किस दर पर उन्हें दिया गया ; और

(ग) क्या खेती के लिये आवश्यक लोहे में सरकार का कोई रियायत देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :  
(क) और (ख) जी नहीं। सन् १९५८-५९ और १९५९-६० की मांग के अनुसार अलॉटमेंट का प्रतिशत क्रमशः २७ और ८० था।

सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में विभिन्न राज्यों को अलॉट की गई मात्रा का विवरण नं० १ सभा की टेबिल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०६]।

इस्पात की नियन्त्रित प्रकारों परिनियत नियन्त्रित मूल्यों (Statutory Controlled Prices) पर, जो कि गजट आफ इंडिया (Gazette of India) में यथा समय नोटिफाई (Notify) होते हैं, बेची जाती हैं। सन् १९५८-५९ और १९५९-६० के मूल्य विवरण नं० २ में जो सभा की टेबिल पर रख दिया गया है, दिखाये गये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०६]।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(a) and (b). No, Sir. The percentage of allotment in relation to the

requirement during 1958-59 and 1959-60 was 27 and 80 respectively.

The quota allotted to various States in 1958-59 and 1959-60 is indicated in Statement placed on the Table. [See Appendix IV, annexure No. 106.]

Controlled categories of steel are sold at statutory controlled prices which are duly notified in the Gazette of India. The prices for the year 1958-59 and 1959-60 are indicated in the Statement placed on the Table. [See Appendix IV, annexure No. 106.]

(c) There is no such proposal at present.

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों को यह लोहे का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है ?

डा० पं० शा० देशमुख : जितनी स्टेटों की मांग है और जितना भी हमारे पास लोहा उपलब्ध होता है उसको इन प्रपोज़न टु दी डिमांड्स बांटा जाता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसानों को कोई रियायती दर पर यह लोहा देने का इंतजाम सोचती है ?

डा० पं० शा० देशमुख : जी नहीं अब तक तो यह नहीं सोचा गया है।

श्री विभूति मिश्र : खेती के उत्पादन के लिये लोहा अत्यधिक जरूरी चीज है और जब किसान के पास साधन न रहे तो सरकार इस संबंध में क्या यह सोच रही है कि थर्ड फाइव ड्रयर प्लान में किसानों को कोई कंसेसशन रेट पर लोहा दे ?

डा० पं० शा० देशमुख : अब तक सरकार ने यह मुनासिब नहीं समझा कि उनको कम बाम में देने की कोई आवश्यकता है।

Shri Rami Reddy: From Statement I, I find that in 1959-60, Bombay was allotted 79,000 odd tons, Madhya Pradesh was allotted 48,000 odd tons, Mysore was allotted 29,228 tons, Uttar Pradesh was allotted 51,350 tons and

so on. May I know the exact basis or principles on which this allotment is made? Is it on population basis or on the basis of the agricultural requirements of each State?

**Dr. P. S. Deshmukh:** As I said in Hindi, first of all we find out the demands of the States and then the availability of the iron and steel that can be distributed. We try to do it in a proportionate way. We fix up a percentage and more or less work on it. My hon. friend is probably concerned about Andhra Pradesh. He will find that between 1958-59 and 1959-60, there is a difference of 2½ times. That shows that in all probability the Andhra Pradesh demand for 1958-59 was not so large as in the case of other States. But when it went up, we gave it 2½ times more.

**Shri Rami Reddy:** May I know what was the demand made by the Andhra Pradesh Government in 1958-59 and 1959-60 and the percentage of the demand allotted to them?

**Dr. P. S. Deshmukh:** I require notice. I have not got details of the demand of every State.

**Shri Rami Reddy:** What is the agency through which the iron and steel is distributed to the ryots? Is it not a fact that complaints are received that the iron is not reaching the peasants in time and at the rates quoted by Government in Statement II?

**Dr. P. S. Deshmukh:** I know there is a lot of difficulty in farmers getting these things and they have often to pay higher prices. But we allot the quotas to State Governments. The distribution is their concern, not ours.

**Shri Venkatasubbaiah:** In view of the fact that so many irregularities are being committed in the distribution of agricultural implements to the peasants, may I know whether the Central Government advised the State Government to give the entire quota to the marketing federations so that these may be distributed through their affiliated marketing committees at the taluka level?

**Dr. P. S. Deshmukh:** We have not found it necessary to give any directions or advice in this case. The State Governments know how to distribute it best. We leave it to their discretion.

**सेठ अचल सिंह :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कोटा देती है और राज्य सरकारें जब मैनुफैक्चरर्स को कोटा देते हैं तो उसमें काफी ब्लैकमार्केटिंग होती है तो उसको रोकने के वास्ते वे क्या कोई पग उठाने वाले हैं ?

**डा० पं० शा० देशमुख :** ऐसी शिकायतें तो सुनने में आती हैं मगर हमारे पास इसका कोई हल नहीं है ।

**श्री बजरज सिंह :** मंत्री महोदय की स्वीकारोक्ति के बाद कि किसानों को कोमत देनी पड़ती है लोहे के लिये वह ज्यादा कीमत होती है और इस तथ्य के बाद कि अब लोहे का उत्पादन देश में बढ़ रहा है तो क्या इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि किसानों की जितनी मांग है उसको पूरा करने के लिये उनको लोहा दिया जाय ?

**डा० पं० शा० देशमुख :** यह तो हमारी हर रोज कोशिश है और स्टेटमेंट से मालूम भी होता है कि काफी मात्रा में हम लोहा और स्टील दे रहे हैं और आशा है कि हमारी ऐसी प्रगति आगे भी बनी रहेगी ताकि यह सवाल ठीक तरह से हल हो जाय ।

**Shri Raghunath Singh:** May I know if there is any diversion of the steel allotted to the agricultural departments? If so, what steps are being taken to stop it?

**Dr. P. S. Deshmukh:** I have heard complaints, but I have no definite information.

**श्री प्रकाश बीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूँ कि जब कृषि कार्यों को इतना महत्व दिया जा रहा है और देश में यह आवश्यक भी

है तो फिर इस प्रकार के उपकरण जो कि कृषि के काम में आते हैं उनके लिये सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि किसानोंको वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सकें और उसके लिये क्या कोई आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

**डा० पं० शा० देशमुख :** जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ सबसिडी के अंश की बात नहीं है लेकिन इस बात के ऊपर हम काफी ध्यान दे रहे हैं कि नये औजार उन्हें आवश्यकतानुसार मिलें और मुनासिब दाम में उन्हें मिलें और उसकी कुछ हम अभी कार्यवाही कर रहे हैं ।

**Shri Yadav Narain Jadhav :** What is the margin of profit allowed? Also, does the quota allotted to the Bombay State include the quota given to the co-operative sugar factories?

**Shri P. S. Deshmukh :** I have no information on this point.

**Shri Viswanatha Reddy :** Is it not a fact that the actual supply of iron and steel comes to a very small percentage of the allotment made to each State? If so, what are the difficulties encountered in actual supply being equal to the full quota allotted?

**Dr. P. S. Deshmukh :** So far as I can follow the hon. Member's question, there are some other priorities which have got to be met first before the total amount of steel available can be allotted for agricultural purposes. Firstly, there are the requirements of power projects, then the requirements of steel processing industries; and, whatever remains is in the third category and we take our own share.

**Shri Viswanatha Reddy :** Assuming that the allotment to a State for agricultural purposes is 100 tons, out of this allotment only about 20 tons are actually supplied to the States. What is the difficulty encountered in supplying the 100 tons allotted?

**श्रीमती लक्ष्मी बाई :** पेपर वालों को और हैंडलूम वालों को उनका कोटा निश्चित करके

कार्ड दे दिये गये हैं जिनके आधार पर वे कहीं से भी अपना सामान खरीद सकते हैं क्या इस इसी प्रकार की सुविधा सरकार लोहे के बारे में भी करने का विचार करती है ?

**डा० पं० शा० देशमुख :** जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश है और वितरण के बारे में भी जो कुछ हम कर सकते हैं कर रहे हैं ।

**श्री विभूति मिश्र :** बिहार को सन् १९५८-५९ में ४३७८ टन और सन् १९५९-६० में ९६८१ टन लोहा दिया गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि जब बिहार की आबादी कई राज्यों से ज्यादा है तो उसको इतना कम कोटा क्यों दिया गया ?

**डा० पं० शा० देशमुख :** मैंने जो इस बारे में आंध्र के लिये जवाब दिया है शायद वही बिहार के लिये भी सही होगा । बिहार की बड़ी मांग नहीं थी इसलिये उसको प्रोपो-शनेट दे दिया गया ।

**Shri Rami Reddy :** The hon. Minister said that the Central Government would first require the State to place a demand; and, then, on the basis of the iron and steel available they will make allotments. If so, what is the difficulty to supply the allotments made to the States? After the steel plants have come into production, does this Ministry consider the feasibility of supplying the full requirements for agricultural purposes?

**Dr. P. S. Deshmukh :** That is our concern. We have always been doing or trying to do that. As a matter of fact, after the meeting that we held with the Steel Controller and the Ministry's representatives, we have been able to increase the supply from 22 per cent, which it was a few years ago, to 27 per cent and make it now 80 per cent or 76 per cent. This is all due to whatever efforts we could make. I could not understand the first part of the question of the hon. Member.

**Mr. Speaker:** The hon. Member only wants to know why even the allotted quota has not been fulfilled by way of supply. He says that the allotment is one thing and the supply is much less. What is it due to?

**Dr. P. S. Deshmukh:** I have no information on that point. I will certainly look into it.

**Shri Tangamani:** I would like to know whether the hon. Minister has got with him the figures of at least the total quantity that has been supplied in the year 1959-60 as against the 3,20,175 tons allocated to the various States.

**Mr. Speaker:** The hon. Member wants to know the total quantity actually supplied as against the allotment of 3 lakhs and odd tons.

**Dr. P. S. Deshmukh:** According to me this has been supplied?

**Mr. Speaker:** Fully?

**Dr. P. S. Deshmukh:** Yes, Sir.

श्री पद्म देव : हिमाचल में कृषि के लिए सरकार की ओर से जितने लोहे की मांग है उसके मुताबिक केन्द्रीय सरकार कोटा स्वीकार नहीं करती। मंत्री महोदय को मालूम है कि वहां शताब्दियों से किसी किस्म का विकास नहीं हुआ है, इसलिए भी वहां लोहे की ज्यादा आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां की जरूरत के मुताबिक कोटा क्यों निर्धारित नहीं किया गया ?

डा० पं० शा० देशमुख : जैसा कि मैंने भी जवाब दिया, हम हर कोशिश करते हैं ज्यादा देने की।

#### Teleprinter Factory

\*1820. { Shri Shree Narayan Das:  
Shri Radha Raman:  
Shri P. C. Borooah:  
Shri B. C. Mullick:  
Shri Kalika Singh:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state

whether any decision with regard to the selection of a consultant and the location for setting up a teleprinter factory in the public sector has been taken?

**The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur):** A decision with regard to the selection of the consultant has been taken but agreement has yet to be finalised.

The location for setting up the factory has not yet been decided and will not be possible until after the formalities of the agreement are completed.

**Shri Shree Narayan Das:** May I know what are the places under consideration for the location of the factory?

**Shri Raj Bahadur:** It is premature for me to state anything about it.

**Shri Shree Narayan Das:** May I know whether the firm of consultants would be settled after inviting tenders or would it be by negotiations?

**Shri Raj Bahadur:** Negotiations or other processes have taken place and the firm has been decided. It is Messrs. Olivetti Co. of Italy.

**Shri P. C. Borooah:** May I know whether the proposed private company with cent per cent. Government capital has been formed? If so, what is the capital and what is the foreign exchange component?

**Shri Raj Bahadur:** It will be 100 per cent. capital and it will be registered as a private limited company.

**Shri P. C. Borooah:** May I know whether a target has been fixed for the production of teleprinters and what will be our requirements under the Third Five Year Plan?

**Shri Raj Bahadur:** I cannot state what the actual requirements will be; but from memory I can state that about 1,000 teleprinters are needed.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल अंग्रेजी भाषा के लिए